

# Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the 'Committee on Publication Ethics'

Online ISSN:2584-184X



## Review Paper

# विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल मीडिया की युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका

विजय सिंह<sup>1\*</sup>, डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़<sup>2</sup>

<sup>1</sup> शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत

<sup>2</sup> प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: \* विजय सिंह

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051775>

सारांश	Manuscript Info.
<p>“विकसित भारत 2047” की परिकल्पना एक ऐसे समावेशी और सशक्त राष्ट्र के निर्माण पर आधारित है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की समान भागीदारी सुनिश्चित हो। इस संदर्भ में युवा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि डिजिटल मीडिया किस प्रकार विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रभावित करता है।</p> <p>अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल मीडिया शिक्षा, सूचना तक पहुँच, कौशल विकास, आर्थिक अवसर और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से युवा आदिवासी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, आत्मविश्वास विकसित करती हैं तथा सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने लगती हैं।</p> <p>हालांकि, डिजिटल विभाजन, तकनीकी साक्षरता की कमी, सामाजिक नियंत्रण और सांस्कृतिक बाधाएँ इस प्रक्रिया को सीमित करती हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डिजिटल मीडिया युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसका प्रभाव तभी व्यापक और स्थायी होगा जब इसे समावेशी नीतियों, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक समर्थन के साथ जोड़ा जाए।</p>	<p>✓ ISSN No: 2584-184X            ✓ Received: 11-10-2025            ✓ Accepted: 28-11-2025            ✓ Published: 30-12-2025            ✓ MRR:3(12):2025;121-125            ✓ ©2025, All Rights Reserved.            ✓ Peer Review Process: Yes            ✓ Plagiarism Checked: Yes</p> <p><b>How To Cite</b>            सिंह व, ह स राठौड़. विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल मीडिया की युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(12):121-125.</p>

**मुख्य शब्द:** विकसित भारत 2047, डिजिटल मीडिया, युवा आदिवासी महिलाएं, सशक्तिकरण, समावेशी विकास

## प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित “विकसित भारत 2047” का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समावेशी, समानता मूलक और सशक्त समाज के निर्माण की परिकल्पना करता है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को विकास की प्रक्रिया में समान अवसर और भागीदारी प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण में विशेष रूप से समाज के वंचित और हाशिए पर स्थित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। युवा आदिवासी महिलाएं इसी वर्ग का

एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनका सशक्तिकरण विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। आदिवासी समाज ऐतिहासिक रूप से भौगोलिक अलगाव, सीमित संसाधनों और सामाजिक उपेक्षा के कारण विकास की मुख्यधारा से पीछे रहा है। इन समुदायों की महिलाओं की स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि वे लैंगिक असमानता, शिक्षा की कमी और सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करती हैं। इस प्रकार, युवा आदिवासी महिलाएं

बहुस्तरीय वंचना की स्थिति में होती हैं, जहाँ उनके लिए अवसरों की उपलब्धता सीमित रहती है।

ऐसे परिदृश्य में डिजिटल मीडिया एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना तक पहुँच आसान हुई है, जिससे युवा आदिवासी महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ ही, डिजिटल मीडिया उन्हें अपनी आवाज व्यक्त करने, सामाजिक नेटवर्क का विस्तार करने और व्यापक समाज से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है।

हालांकि, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सशक्तिकरण की यह प्रक्रिया सरल और समान नहीं है। डिजिटल विभाजन, तकनीकी साक्षरता की कमी, सामाजिक नियंत्रण और सांस्कृतिक बाधाएँ इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। कई बार डिजिटल संसाधनों तक पहुँच होते हुए भी उनका प्रभावी उपयोग संभव नहीं हो पाता।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल मीडिया युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार भूमिका निभा रहा है। यह अध्ययन सशक्तिकरण को एक बहुआयामी और संदर्भ-निर्भर प्रक्रिया के रूप में समझते हुए अवसरों, चुनौतियों और सामाजिक परिवर्तन के अंतःसम्बंधों को उजागर करने का प्रयास करता है।

### विकसित भारत 2047 और समावेशी विकास की अवधारणा

“विकसित भारत 2047” की परिकल्पना भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक देश को एक विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक दीर्घकालिक दृष्टि प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, समान अवसर, लैंगिक समानता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे तत्वों को भी समान महत्व दिया गया है। इस प्रकार, विकसित भारत की अवधारणा एक समग्र (holistic) विकास मॉडल पर आधारित है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

समावेशी विकास इस दृष्टि का एक केंद्रीय तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि विकास की प्रक्रिया में किसी भी वर्ग को पीछे न छोड़ा जाए, विशेष रूप से वे समुदाय जो ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहे हैं, जैसे कि आदिवासी समाज और महिलाएं। समावेशी विकास केवल संसाधनों के वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अवसरों की समान उपलब्धता, सामाजिक भागीदारी और सम्मानजनक जीवन की गारंटी से भी जुड़ा हुआ है।

युवा आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में समावेशी विकास का महत्व और भी बढ़ जाता है। वे न केवल सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित हैं, बल्कि लैंगिक असमानता के कारण अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करती हैं। ऐसे में उनका सशक्तिकरण विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।

डिजिटल युग में समावेशी विकास की अवधारणा में डिजिटल समावेशन (digital inclusion) एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। डिजिटल मीडिया और तकनीक के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुँच को सरल बनाया जा

सकता है। यह विशेष रूप से दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पारंपरिक संसाधनों की पहुँच सीमित होती है।

हालांकि, समावेशी विकास की इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे डिजिटल विभाजन, तकनीकी असमानता और सामाजिक बाधाएँ। इसलिए, केवल तकनीकी विस्तार पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सभी वर्गों को इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता और अवसर प्राप्त हों।

अतः विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए समावेशी विकास को एक प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया आवश्यक है, जिसमें डिजिटल मीडिया और तकनीक के माध्यम से युवा आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

### डिजिटल मीडिया: सशक्तिकरण का आधुनिक माध्यम

डिजिटल युग में डिजिटल मीडिया सशक्तिकरण के एक प्रभावी और आधुनिक माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है। यह केवल सूचना और संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रसार ने समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से वंचित समूहों, के लिए नए अवसरों का निर्माण किया है।

डिजिटल मीडिया की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुलभता और त्वरितता है। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी समय और स्थान पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। युवा आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और रोजगार से संबंधित जानकारी तक आसानी से पहुँच प्रदान करता है। इससे उनकी जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति और संवाद का मंच भी प्रदान करता है। वे अपने विचारों, अनुभवों और समस्याओं को साझा कर सकती हैं, जिससे उनकी सामाजिक पहचान और आत्मविश्वास मजबूत होता है। यह उन्हें केवल सूचना प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि सक्रिय सहभागी बनाता है।

आर्थिक दृष्टि से भी डिजिटल मीडिया सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से महिलाएं डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन व्यवसाय और कौशल विकास के अवसरों से जुड़ सकती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है और वे अपने जीवन के निर्णय अधिक आत्मनिर्भरता के साथ ले पाती हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से डिजिटल मीडिया “ज्ञान और शक्ति” के नए संबंधों को स्थापित करता है। जो व्यक्ति जानकारी और तकनीक तक पहुँच रखता है, वह सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनता है। इस प्रकार, डिजिटल मीडिया सामाजिक असमानताओं को कम करने का माध्यम भी बन सकता है, बशर्ते इसकी पहुँच समान रूप से सुनिश्चित की जाए।

हालांकि, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि डिजिटल मीडिया का प्रभाव स्वतः सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं होता। इसके लिए डिजिटल साक्षरता, सामाजिक स्वीकृति और संरचनात्मक समर्थन आवश्यक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि डिजिटल मीडिया आधुनिक समय में सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो विशेष रूप से युवा आदिवासी महिलाओं के लिए नए अवसरों और संभावनाओं का द्वार खोलता है, और उन्हें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

### युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में डिजिटल मीडिया की भूमिका

डिजिटल मीडिया ने युवा आदिवासी महिलाओं के जीवन में सशक्तिकरण की प्रक्रिया को एक नई दिशा प्रदान की है। यह केवल सूचना का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अवसरों, सहभागिता और पहचान निर्माण का एक प्रभावी साधन बनकर उभरा है। विशेष रूप से विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल मीडिया इन महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले, डिजिटल मीडिया शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से युवा आदिवासी महिलाएं ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो, डिजिटल कंटेंट और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए ज्ञान अर्जित कर रही हैं। इससे उनकी शैक्षिक पहुँच बढ़ी है और वे पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नई सीख प्राप्त कर रही हैं। दूसरा, डिजिटल मीडिया आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। कुछ महिलाएं डिजिटल माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार भी कर रही हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।

तीसरा, डिजिटल मीडिया सामाजिक सशक्तिकरण को भी मजबूत करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म महिलाओं को अपनी बात रखने, अनुभव साझा करने और सामाजिक नेटवर्क का विस्तार करने का अवसर देते हैं। इससे उनकी सामाजिक पहचान (identity) विकसित होती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

चौथा, डिजिटल मीडिया राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता को बढ़ाता है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। इससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं।

पाँचवां, डिजिटल मीडिया मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण में भी योगदान देता है। जब महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होती हैं और अपनी अभिव्यक्ति करती हैं, तो उनके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वे स्वयं को एक सक्षम और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखने लगती हैं।

हालांकि, इस सशक्तिकरण की प्रक्रिया में कुछ सीमाएँ भी हैं। डिजिटल विभाजन, तकनीकी साक्षरता की कमी, सामाजिक नियंत्रण और साइबर जोखिम जैसे कारक इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि डिजिटल मीडिया युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन्हें शिक्षा, आर्थिक अवसर, सामाजिक सहभागिता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। किंतु इसके प्रभाव को व्यापक और स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है कि डिजिटल संसाधनों की समान पहुँच, प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन सुनिश्चित किया जाए।

### चुनौतियाँ

यद्यपि डिजिटल मीडिया युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी प्रक्रिया कई संरचनात्मक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों से घिरी हुई है। ये चुनौतियाँ न केवल डिजिटल माध्यमों तक पहुँच को सीमित करती हैं, बल्कि उनके प्रभावी उपयोग को भी प्रभावित करती हैं।

सबसे प्रमुख चुनौती डिजिटल विभाजन है। जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता, कमजोर नेटवर्क और स्मार्टफोन जैसे उपकरणों की कमी के कारण युवा महिलाएं डिजिटल संसाधनों तक समान रूप से पहुँच नहीं बना पातीं। इसके साथ ही, परिवार के भीतर संसाधनों के वितरण में भी लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, जहाँ पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है।

दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती तकनीकी साक्षरता की कमी है। कई युवा आदिवासी महिलाएं डिजिटल उपकरणों का उपयोग तो करती हैं, लेकिन उन्हें इनका पूर्ण और प्रभावी उपयोग करने का प्रशिक्षण नहीं मिलता। इससे वे डिजिटल मीडिया के संभावित लाभों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पातीं।

तीसरी चुनौती सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ हैं। कई समुदायों में पारंपरिक मान्यताएँ और पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित करती हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट के उपयोग पर परिवार या समाज द्वारा नियंत्रण रखा जाता है, जिससे उनकी डिजिटल भागीदारी प्रभावित होती है।

चौथी चुनौती साइबर सुरक्षा और जोखिम से जुड़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी, साइबर बुलिंग, गोपनीयता का उल्लंघन और ऑनलाइन शोषण जैसी समस्याएँ महिलाओं के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। इन जोखिमों के कारण कई महिलाएं डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाए रखती हैं।

पाँचवीं चुनौती भाषाई और सांस्कृतिक अवरोध भी है। अधिकांश डिजिटल सामग्री प्रमुख भाषाओं (जैसे हिंदी या अंग्रेजी) में उपलब्ध होती है, जबकि कई आदिवासी महिलाएं अपनी स्थानीय भाषाओं में अधिक सहज होती हैं। इससे उनके लिए डिजिटल सामग्री को समझना कठिन हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक सीमाएँ भी एक महत्वपूर्ण बाधा हैं। इंटरनेट डेटा, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल संसाधनों की लागत कई परिवारों के लिए वहन करना कठिन होता है, जिससे डिजिटल सहभागिता सीमित रहती है।

अतः यह स्पष्ट है कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से सशक्तिकरण की प्रक्रिया कई चुनौतियों से प्रभावित होती है। इन चुनौतियों को दूर किए बिना डिजिटल मीडिया के पूर्ण लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि डिजिटल समावेशन, प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इन बाधाओं को कम किया जाए, ताकि युवा आदिवासी महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।

### समाजशास्त्रीय विश्लेषण

युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में डिजिटल मीडिया की भूमिका को समझने के लिए इसे केवल तकनीकी परिवर्तन के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक समाजशास्त्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा आवश्यक है। यह प्रक्रिया संरचना (structure), एजेंसी (agency),

संस्कृति, शक्ति-संबंधों और सामाजिक असमानताओं के अंतःसम्बंधों से निर्मित होती है।

सबसे पहले, डिजिटल मीडिया सशक्तिकरण को एजेंसी और संरचना के अंतःक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। युवा आदिवासी महिलाएं डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अपनी अभिव्यक्ति, ज्ञान और सहभागिता को बढ़ाती हैं, जो उनकी एजेंसी को मजबूत करता है। किन्तु यह एजेंसी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि सामाजिक मानदंडों, पारिवारिक नियंत्रण और संसाधनों की उपलब्धता जैसी संरचनात्मक सीमाओं से प्रभावित होती है।

दूसरा, डिजिटल मीडिया को एक शक्ति और ज्ञान के क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। जो महिलाएं डिजिटल जानकारी और तकनीकी कौशल प्राप्त कर लेती हैं, वे सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनती हैं। इस प्रकार, ज्ञान तक पहुँच शक्ति का स्रोत बन जाती है। हालांकि, जिनके पास यह पहुँच नहीं है, वे इस प्रक्रिया से बाहर रह जाती हैं, जिससे असमानताएँ बनी रहती हैं।

तीसरा, डिजिटल मीडिया पहचान के निर्माण और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवा आदिवासी महिलाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान, जीवनशैली और अनुभवों को प्रस्तुत करती हैं। इससे उनकी सामाजिक दृश्यता बढ़ती है, लेकिन साथ ही वे मुख्यधारा की संस्कृति के प्रभाव में भी आती हैं, जिससे पहचान का एक नया मिश्रित स्वरूप विकसित होता है।

चौथा, यह प्रक्रिया परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को भी दर्शाती है। डिजिटल मीडिया आधुनिक जीवनशैली और नए अवसरों को प्रस्तुत करता है, जबकि जनजातीय समाज पारंपरिक मूल्यों और रीति-रिवाजों पर आधारित होता है। युवा महिलाएं इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया उत्पन्न होती है।

पाँचवाँ, डिजिटल मीडिया सामाजिक असमानताओं के पुनरुत्पादन और कमी दोनों में भूमिका निभाता है। एक ओर यह अवसरों का विस्तार करता है, वहीं दूसरी ओर यह उन लोगों को अधिक लाभ देता है जिनके पास पहले से संसाधन और शिक्षा उपलब्ध है। इस प्रकार, यह असमानताओं को कम करने के साथ-साथ उन्हें पुनः उत्पन्न भी कर सकता है।

अतः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि डिजिटल मीडिया युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसका प्रभाव संदर्भ-निर्भर और बहुआयामी है। इसे समझने के लिए आवश्यक है कि हम तकनीकी पहलुओं के साथ-साथ सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संदर्भ और शक्ति-संबंधों को भी ध्यान में रखें।

### निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल युग में डिजिटल मीडिया युवा आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है। यह केवल सूचना और संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, आर्थिक अवसर, सामाजिक सहभागिता, आत्म-अभिव्यक्ति और जागरूकता के नए आयाम प्रदान करता है। इसके माध्यम से युवा आदिवासी महिलाएं अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय

भूमिका निभाने लगती हैं और उनकी आकांक्षाओं, पहचान तथा आत्मविश्वास में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलता है।

हालांकि, यह सशक्तिकरण की प्रक्रिया सरल और समान रूप से वितरित नहीं है। डिजिटल विभाजन, तकनीकी साक्षरता की कमी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिबंध, तथा साइबर जोखिम जैसे कारक इस प्रक्रिया को सीमित करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनके प्रभावी उपयोग के लिए सामाजिक स्वीकृति, प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन भी आवश्यक है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि डिजिटल मीडिया सशक्तिकरण की एक बहुआयामी और संदर्भ-निर्भर प्रक्रिया को जन्म देता है, जिसमें एजेंसी और संरचना के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है। यह एक ओर अवसरों का विस्तार करता है, वहीं दूसरी ओर असमानताओं को भी उजागर करता है।

अतः "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि डिजिटल समावेशन को प्राथमिकता दी जाए, विशेष रूप से युवा आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में। इसके लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार, सुलभ इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता, और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना अनिवार्य है। अंततः, डिजिटल मीडिया तभी वास्तविक और स्थायी सशक्तिकरण का माध्यम बन सकता है जब इसे सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ समन्वित किया जाए। यही दृष्टिकोण युवा आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उनकी सार्थक भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।

### सन्दर्भ :

1. आहूजा राम. भारतीय समाज. जयपुर: रावत पब्लिकेशन; 2014.
2. आहूजा राम. समाजशास्त्र के सिद्धांत. जयपुर: रावत पब्लिकेशन; 2016.
3. देसाई एआर. भारतीय समाज का समाजशास्त्र. नई दिल्ली: पॉपुलर प्रकाशन; 2011.
4. दुबे श्यामाचरण. परंपरा, आधुनिकता और परिवर्तन. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट; 2004.
5. जोशी माया. महिला अध्ययन: सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन; 2018.
6. पाण्डेय राजेंद्र. सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन; 2017.
7. शर्मा शशि. डिजिटल मीडिया और भारतीय समाज. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन; 2019.
8. सिंह सीमा. महिला, मीडिया और समाज. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन; 2016.
9. सिंह योगेन्द्र. आधुनिक भारतीय समाज. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2007.
10. सिंह योगेन्द्र. सामाजिक परिवर्तन: सिद्धांत एवं यथार्थ. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2012.
11. भार्गव राजीव. सामाजिक न्याय और भारतीय लोकतंत्र. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2010.

12. कुमार विवेक. जाति, लैंगिकता और सामाजिक असमानता. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन; 2015.
13. मिश्र कैलाशचंद्र. महिला सशक्तिकरण: भारतीय परिप्रेक्ष्य. वाराणसी: भारतीय ज्ञानपीठ; 2018.
14. तिवारी प्रमिला. डिजिटल युग में महिला चेतना. लखनऊ: नवलेख प्रकाशन; 2019.
15. भारत सरकार. विकसित भारत @2047: दृष्टि दस्तावेज़. नई दिल्ली: नीति आयोग; 2023.
16. नीति आयोग. SDGs, Gender Equality and Digital Inclusion in India. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2022.
17. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). भारत में लैंगिक समानता और डिजिटल परिवर्तन. नई दिल्ली: यूएनडीपी इंडिया; 2021.
18. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO). शिक्षा और डिजिटल पहुंच पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2019.
19. राष्ट्रीय महिला आयोग. महिला अधिकार और डिजिटल सुरक्षा. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2020.
20. Anderson B. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Rev ed. London: Verso; 2006.
21. Castells M. The rise of the network society. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010.
22. Castells M. Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age. Cambridge: Polity Press; 2012.
23. Sen A. Development as freedom. New Delhi: Oxford University Press; 1999.
24. Nussbaum MC. Creating capabilities: The human development approach. Cambridge: Harvard University Press; 2011.
25. Kabeer N. Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Dev Change. 1999;30(3):435–464. doi:10.1111/1467-7660.00125
26. UN Women. Gender equality and women's empowerment in the digital age. New York: United Nations; 2020.
27. UNESCO. I'd blush if I could: Closing gender divides in digital skills through education. Paris: UNESCO Publishing; 2019.
28. World Bank. World development report 2016: Digital dividends. Washington DC: World Bank Publications, 2016.
29. GSMA. The mobile gender gap report. London: GSM Association; 2020.
30. Huyer S, Carr M. Information technology and women's empowerment. New York: United Nations Development Programme; 2002.
31. True J. The political economy of violence against women. Oxford: Oxford University Press; 2016.
32. Gurumurthy A, Chami N. Gender equality in the information society. Bangalore: IT for Change; 2014.
33. Gurumurthy A. Digital empowerment: Opportunities and challenges for women. Econ Polit Wkly. 2018;53(17):43–49.
34. Bhatia R, Bhabha J. India's digital divide and gender inequality. Harv Hum Rights J. 2017;30:1–29.

#### Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.